संख्या:51/2024/150/35-4-2024/35-4099/13/2022

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक: 08 फरवरी,2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद-गोण्डा में शासनादेश संख्या-240/2022/848/35-4-2022/001-35-4099/13/2022, दिनांक 05 अगस्त 2022 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की अनुमोदित लागत रू0 2461.99 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 615.50 लाख तथा शासनादेश संख्या-140/2023/79/35-4-2023/001-35-4099/13/2022, दिनांक 24 फरवरी, 2023 के माध्यम से द्वितीय किश्त के रूप में रू0 615.50 लाख तथा शासनादेश सं0-671/2023/1775/35-4-2023/001-35-4099/13/2022, दिनांक 13 जून, 2023 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 615.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस प्रकार अब तक कुल रू. 1846.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी गोण्डा के पत्र सं0-686/अर्थ एवं संख्या/त्व0आ0वि0/2022-23, दिनांक 03 नवम्बर, 2023 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित लागत रू0 2461.99 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का पूर्ण उपभोग एवं बचत के रूप में रू. 0.32 लाख की धनराशि इंगित की गयी है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि एवं बचत रू. 0.32 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में देय अवशेष धनराशि रू0 615.17 लाख (रूपये छः करोड़ पन्द्रह लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त धनराशि	बचत की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
मैजापर चीनी मिल के सम्पर्क मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	2461.99	1846.50	0.32	615.17

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 अगस्त, 2022, दिनांक 24 फरवरी, 2023 तथा दिनांक 13 जून, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 6,15,17,000 (रूपये छ: करोड़ पन्द्रह लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या:51/2024/150(1)/35-4-2024/35-4099/13/2022तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
11-सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, लखनऊ।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
14- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in